

THE
PARLIAMENTARY DEBATES
OFFICIAL REPORT

IN THE SIXTY-THIRD SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 12th February, 1968/r/ze 23rd Magna, 1889 Saka

RAJYA SABHA

Monday, the 12th February, 1968/rfo 23rd
Magna, 1889 (Saka)

The House met at forty minutes past twelve of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

**PRESIDENT'S ADDRESS LAID ON
THE TABLE**

SECRETARY : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 12th February, 1968.

(Text of the President's Address in Hindi)

संसद् सदस्यगण,

नये वर्ष के इस प्रथम अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

पिछला साल कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था। लगातार दूसरे साल भी देश ने अभूतपूर्व सूखे और अभाव का सामना किया। पहले के अकालों के विध्वंस को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा गौरव है कि समूचे राष्ट्र ने एक जुट होकर करोड़ों देशवासियों के जीवन पर आये भयंकर खतरे का सामना कर सफलता प्राप्त की। इस सफलता के कई विशेष कारण हैं : केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समयोचित और महत्वपूर्ण कार्य, ऐच्छिक संस्थाओं की निष्ठापूर्ण सेवा, मित्र राष्ट्रों की सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों की कुशलता और उनके कठिन परिश्रम तथा सूबाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की अटूट हिम्मत और सहस का बल।

एक साल पहले भविष्य अन्वकारपूर्ण दीखता था लेकिन निराशा के बादल अब हटने लगे हैं। इस साल अनाज की पैदावार पिछले सभी सालों से ज्यादा होने की उम्मीद है। अमतीर पर यह अन्दाज लगाया जा रहा है कि इस साल लगभग साढ़े नौ करोड़ टन अनाज पैदा होगा जो 1966-67 की तुलना में दो करोड़ टन ज्यादा और 1964-65 से, जब कि बहुत ज्यादा अनाज पैदा हुआ था 60 लाख टन ज्यादा होगा। पैदावार की इस वृद्धि से खाद्य स्थिति में सुधार की आशा है। फिर भी इस साल जो उपज होगी उसका बहुत अधिक हिस्सा तो सरकारी और निजी खाली गोदामों को भरने में चला जाएगा। खाद्य स्थिति में स्थिरता लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि काफी बड़ा बफर स्टॉक तैयार किया जाए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि नियंत्रित दाम पर सरकार की ओर से अनाज का बटवारा जारी रखा जाए। इन्हीं उद्देश्यों के लिए सरकार अपने देश में अन्न संप्रह के लिए बराबर कोशिश कर रही है और प्रयास है कि 30 लाख टन का एक बफर स्टॉक तैयार किया जाय। इन सब के लिए देश में पैदावार को बहुत अधिक गतिशील बनाने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद बाहर से कुछ आयात करना जरूरी होगा।

यह सही है कि अच्छे मौसम की वजह से पैदावार बढ़ी है लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कृषि की पैदावार में जो सफलता हमें मिली है उसमें खेती के नए तरीके का बहुत बड़ा योगदान है। 1966-67 में 50 लाख एकड़ भूमि पर अधिक उपज देने वाले बीज बोये गए थे। पिछली खरीफ की फसल में

3

60 लाख एकड़ भूमि पर यह बाज बाया गया था और अनुमान है कि मौजूदा रबी की फसल में 90 लाख एकड़ भूमि में यह बीज बोया गया है। कपास, जूट, ईख, तम्बाकू, मूंगफली जैसी व्यापारिक फसलों की पैदावार भी बढ़ने की आशा है। 30 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि पर लघु सिंचाई कार्यक्रम लागू होगा। नाइट्रोजन पूरक खाद का उपयोग भी बहुत अधिक बढ़ा है और 1965-66 की तुलना में इसकी खपत इस साल लगभग दूनी हो गई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग तीन चौथाई अधिक इलाके में पीछा रक्षण की व्यवस्था की गई है। ट्रैक्टर, बिजली से चलने वाले खेती के उपकरण, पम्प, डीजल इंजन और खेती के दूसरे औजार बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को दिए जाने की व्यवस्था की गई है। खेती के लिए उधार पर रुपये देने की व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। खेती संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण, खोज और विस्तार के कार्यक्रम को अमल में लाने के बारे में भी लगातार तरक्की हो रही है। खेती के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है कम से कम समय में अपने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना।

खेतों में पैदावार बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 1966-67 में जो हमारी आय थी उसमें 10.8 प्रतिशत वृद्धि की इस साल आशा है। खेती की पैदावार बढ़ने की वजह से दामों का ऊपर बढ़ना भी कुछ कम हुआ है। 1966 में थोक कीमतें 16 प्रतिशत बढ़ गयी थीं किन्तु मौजूदा साल में इनकी वृद्धि 5.7 प्रतिशत हुई है। मूल्यों में स्थिरता आने के अच्छे आसार दिखाई पड़ रहे हैं फिर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा, मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए यह जरूरी होगा कि अनाज के सरकारी वितरण की व्यवस्था कायम रहे और राजकोष, आर्थिक तथा आय संबंधी नीति पर हमारा अनुशासन बना रहे।

पिछले दो सालों में जो भयंकर सूखा पड़ा उसका असर कारखानों की पैदावार पर

भा हुआ। कारखाने जो खत की पैदावार पर मुनहमिर थे उनको कच्चा माल पूरा नहीं मिल सका और आमदनी में कमी होने के कारण मांग भी कुछ गिर गई। कुछ पूंजी और उत्पादक माल बनाने वाले कारखानों के सामने भी कम मांग की समस्या आई चूंकि पूंजी लगाने की शक्ति में कमी हो गई थी। औद्योगिक विस्तार की गति धीमी होने की वजह से रोजगार हासिल करने में खासकर दुनरमन्द लोगों को दिक्कत हुई। सरकार ने बाहर भेजने और देश में खपत के लिए कुछ चीजों की पैदावार बढ़ाने के लिए खास कदम उठाये हैं, इनमें कर्ज की शर्तों में ढील देना, सरकारी कारखानों द्वारा अग्रिम आर्डर देना और जो चीजें देश में बनाई जाती हैं उनको विदेशों से नहीं मंगाने की नीति शामिल है। खेती की पैदावार बढ़ने से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उससे यह आशा की जाती है कि अगले साल औद्योगिक उत्पादन की बहुत सी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

पिछले दो सालों में लागत और मूल्य के बराबर बढ़ते रहने तथा खेती की पैदावार में बहुत कमी होने के कारण हमारे निर्यात को धक्का पहुंचा। लेकिन अभी अन्न की अच्छी उपज तथा कारखानों के लिए खेती से अधिक कच्चे माल प्राप्त होने के कारण अगले साल हमारे निर्यात के बढ़ने की आशा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के 7 महीनों में 1966-67 के इन सात महीनों की तुलना में हमारा निर्यात 5.7 प्रतिशत अधिक रहा है। इंजीनियरी के सामान बनाने वाले कारखानों के पास निर्यात के लिए काफी आर्डर मिल चुके हैं। औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने से यह आशा की जाती है कि विदेशों के बाजारों के लिए हम अधिक चीजें बनाने में समर्थ हो सकेंगे।

तरह तरह के सामान बनाने और उत्पादन में वृद्धि, माल बेचने की कला के विकास और क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पादकों और निर्माताओं को सरकार बराबर सहायता देती रही है। अपने देश के उत्पादन के निर्यात को

बढ़ाने और विदेशों में हमारे माल की ज्यादा मांग बढ़ाने की कोशिश हुई है। विदेश स्थित हमारे मिशनों से इस के लिए बराबर रोज-ब-रोज सम्पर्क रखा जा रहा है और द्विदेशीय करार तथा बहुपक्षीय वार्ता भी हुई है। समाजवादी देशों के साथ जो हमारे करार हुए हैं उनसे हमारे व्यापार का बराबर विस्तार होता रहेगा। कैंनेडी द्वारा प्रारंभ करारों के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर हमारे निर्यात-कर्ताओं को माल भेजने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के साथ जो हमारा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग करार हुआ है उससे पारस्परिक व्यापार बढ़ेगा और दूसरे विकासशील देशों के साथ हमारे व्यापारिक सहयोग के विस्तार का आघार प्राप्त होगा। निर्यात का विस्तार हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है और उसे सदा बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्यात में अधिक आयात तथा विदेशी ऋण को चुकाने के भार, अनाज के आयात और निर्यात के लिए जो चीजे तैयार की जाती हैं उनके लिए विदेशी माल को मंगाने के कारण हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पिछले साल कठिन रही। विदेशी ऋण पर खर्च की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में सरकार ने मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता मांगी है। इस और हमें कुछ हद तक सहायता प्राप्त भी हुई और चर्चा आगे चल रही है। विदेशी मुद्रा की जो राशि अपने पास थी उसमें कमी हुई इसलिए यह जरूरी हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कुछ और अल्प-कालीन सहायता ली जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक सफलता पूर्वक चलाने की किसी भी योजना के लिए अपने व्यापारिक जहाजों का विकास और बंदरगाहों की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं—तूतीकोरन और मंगलौर बंदरगाहों का विकास और हल्दिया गोदी का निर्माण,

बंदरगाहों पर जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार, हिन्दुस्तान शिपयार्ड का पुनर्गठन और आधुनिक बनाया जाना। कोचीन में सरकारी क्षेत्र द्वारा दूसरे शिपयार्ड की स्थापना की गई है जहां 66,000 डेडवेट टन के जहाजों का निर्माण हो सके और 85,000 डेडवेट टन तक के जहाजों की मरम्मत की सुविधा हो। जहां तक हमारे व्यापारिक जहाजों की भारवाहन क्षमता का प्रश्न है वह लगभग 20 लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन तक पहुंच गयी है। सरकार ने एक ऐसे आयोग की भी स्थापना की है जो बड़े बड़े बन्दरगाहों की आर्थिक समस्याओं पर विचार करे और उनके आधुनिक बनाये जाने के संबंध में सुझाव दे।

परिवार नियोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा किए बगैर वार्षिक सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं होगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम में जोरदार प्रगति हुई। देहाती और शहरी आबादी में बहुत से नए वर्षों के लोगों ने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया। अनुमान है कि 28.50 लाख से अधिक स्त्री और पुरुष विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं। अब तक किसी एक वर्ष की जो संख्या रही है, उससे यह संख्य कहीं ज्यादा है। फिर भी, वार्षिक जन्म दर को एक हजार में लगभग 40 से 25 तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इससे भी ज्यादा और लगातार कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह इरादा किया गया है कि अगले वर्ष 60 लाख अतिरिक्त स्त्री-पुरुषों को परिवार नियोजन के तरीकों और सेवाओं की परिधि में ले आया जाए। आबादी को नियंत्रित करने के कुछ अन्य उपायों पर भी सरकार विचार कर रही है।

भविष्य की ओर देखते हुए सरकार के सामने सबसे बड़ा काम अर्थ-व्यवस्था को नष्ट सिरे से गतिशील बनाना है। पिछले दो वर्षों

में इसे जो ज़बर्दस्त धक्के लगे हैं, उन्हें पार कर यह अब संभल रही है। सरकार का ब्याल है कि योजना के तरीके से ही कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा में देश आगे जा सकता है।

योजना कमीशन चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में लगा हुआ है; यह योजना अब अप्रैल 1969 से चालू होगी। इस बीच विकास संबंधी आयोजन वार्षिक योजनाओं के आधार पर होता रहा है। 1968-69 वार्षिक योजना जल्दी ही आपके सामने रखी जाएगी। सरकार और योजना कमीशन, दोनों ही स्वाभाविक रूप से इसके लिए उत्सुक हैं कि योजना समय पर तैयार हो जाए ताकि 1968-69 के बजट में उसे शामिल किया जा सके।

हमें अपनी योजनाओं को तैयार करने के लिए कई सवालों पर ध्यान देना है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: संसाधनों को इकट्ठा करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग-धंधों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग करना। सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में काफी हद तक बचत किए बगैर आंतरिक संसाधनों को अच्छी तरह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम आत्म-संयम से काम लें और कम खर्च कर बचत करें क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कारगर ढंग से संसाधन इकट्ठे किए जा सकें, इसके लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है जैसे कि टैक्स के कानून सरल कर दिए जाएं, टैक्स की प्रक्रिया में सुधार किया जाए और समाहरण तंत्र को समुन्नत किया जाए।

सरकारी क्षेत्र की क्षमता को फौरन बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति सरकार सजग है विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं ने जो सलाह

दी है, उसके संदर्भ में सरकार इस क्षेत्र के गठन और उसमें होने वाले कार्य की समीक्षा कर रही है। अच्छा प्रबंध, कर्मचारियों के संबंध में अधिक युक्तियुक्त और सुविचारित नीति, श्रमिकों के साथ सुधरे हुए संबंध और वरीयताओं (प्रायोरिटीज) तथा मूल्यांकनों को दृढ़ता से लागू करके प्रभावकारी तरीके से क्रिफायत करने के संबंध में खाम तौर से ध्यान दिया जा रहा है।

सदस्यों को याद होगा कि संसद् के पिछले अधिवेशन में उप-प्रधान मंत्री ने ग्राम बीमा को सामाजिक नियंत्रण में लाने के बारे में सरकार के निर्णय पर एक बयान दिया था। सरकार का इरादा है कि उस बयान में जो निर्णय बताए गए थे, उन पर अमल करने के लिए चालू सत्र में एक बिल पेश किया जाए।

हमारे आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने को सरकार जो महत्व देती है, उसका मीने जिक्र किया। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति यह है कि हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में, सरकारी मशीनरी और उद्योग में उत्पादक तथा रचनात्मक तालमेल हो।

समीक्षाधीन वर्ष में थुम्बा इक्वाटोरियल राकेट लॉन्चिंग स्टेशन औपचारिक रूप से समर्पित किया गया। केंद्र से जो पहला रोहिणी राकेट तैयार किया गया था उसे थुम्बा से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। अहमदाबाद में एक्सपेरीमेंटल सैटलाइट कम्प्यूतिकेशन अर्थ स्टेशन पूरा कर लिया गया है और अरबी में एक नया स्टेशन तैयार किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि एटमी शक्ति के क्षेत्र में तारापुर का एटामिक पावर प्रोजेक्ट इस वर्ष आरंभ कर दिया जाएगा। दो और एटामिक पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हमारा प्रशासनिक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वह न सिर्फ जरूरतों को ही पूरा करे बल्कि लोगों का विश्वास भी प्राप्त करे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। उसने कई रिपोर्ट दी हैं जिनमें व्यापक रूप से लोगों ने दिलचस्पी ली है। हमारे देश में इस तरह की व्यापक जांच पहली बार की गई है। इस आयोग के सामने नागरिकों की शिकायतें दूर करने की समस्या थी और उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की हैं। सरकार ने अब यह फैसला किया है कि एक ऐसे सांविधिक तंत्र की स्थापना की जाए जो कुप्रशासन से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार और अन्याय की कथित शिकायतों की जांच करे। इस तंत्र का अध्यक्ष होगा एक लोकपाल जिसे केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के प्रशासनिक कार्य से उत्पन्न होने वाले आरोपों की जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह लोकपाल लोकयुक्त के दर्जे के दो अन्य प्राधिकारियों के कार्य संचालन में भी तालमेल रखेगा। पहला तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा और दूसरा सचिवों के दर्जे से कम दर्जे के केंद्रीय सरकारी नौकरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। संसद् के वर्तमान सत्र में इस आशय का एक बिल पेश किया जाएगा।

हमारे राष्ट्रीय जीवन के कुछ खास पहलुओं पर सरकार को निरंतर चिंता बनी रहती है। बेरोजगारी स्वाभाविक रूप से एक ऐसा विषय है जिससे परेशानी होती है और खास तौर से पढ़े-लिखे और तकनीकी विज्ञान की दृष्टि से योग्य नौजवानों की। फिर भी हमें यह समझना है कि इसके कोई सरल और अल्प-कालिक समाधान नहीं हैं। हमारी आर्थिक उन्नति से रोजगार के जो संवर्द्धन अवसर प्राप्त होंगे, उनसे ही ये समस्याएं हल की जा सकती हैं क्योंकि ऐसा करने से शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों से निकले

हुए लोगों को खपाया जा सकेगा। इसके साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या को भी ध्यान में रखना होगा। भविष्य में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में योजना कमीशन समीक्षात्मक पुनरीक्षण कर रहा है। इस बीच, सरकार को यह पूरी आशा है कि हमारे नव युवा स्त्री और पुरुष, जो श्रम की गरिमा को पहचानते हैं, इस तरह के रोजगार के अवसरों को स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाएंगे जो अब सुलभ हैं चाहे वे कार्य उनकी तकनीकी योग्यता के समकक्ष न बैठते हों।

हमारे समाज के अब तक के अर्थिकसिंत वर्गों—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और पिछड़ी जातियों—की सामाजिक-आर्थिक उन्नति सरकार के लिए अत्यंत रुचि और चिंता का विषय रहा है। हालांकि उनकी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया गया है, तो भी सरकार यह जानती है कि बहुत कुछ करना बाकी है। इस लिहाज से भी, हमारी इस समस्या का आखिरी उत्तर हमारी अर्थ-व्यवस्था के जल्दी समुन्नत होने में ही निहित है।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों ही दृष्टियों से आर्थिक उन्नति और बढ़ोतरी के विषय में हमारी सारी आशाएं इस पर निर्भर करती हैं कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करें, हमारे देशवासी परिश्रम करें, उनमें आत्मानुशासन की भावना जागे, उनके श्रम से उत्पादन बढ़े और उद्योग-घंटों में शांति बनी रहे।

यह चिंता का विषय है कि विभाजक शक्तियां सिर उठाती रही हैं जिसके कारण क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पर झगड़े और फिसाद हुए हैं। यह मामला राष्ट्र के लिए गहरी चिंता का विषय है जो दलगत संबंधों से ऊपर है। यह मानकर ही संसद् के दोनों सदनों ने सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रयत्नों का स्पष्ट समर्थन किया था।

देश के विभिन्न भागों में हुई बड़ी-बड़ी घटनाओं की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व-न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमीशन की नियुक्ति से सरकार के इस दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है कि वह अपनी भरपूर कोशिश से विध्वंसकारी शक्तियों को मिटाने के लिए तत्पर है।

यह स्वाभाविक है कि हमारे जैसे बड़े देश में कुछ-न-कुछ समस्याएं यहां-वहां लोगों को आंदोलित करती रहें। फिर भी, हमारे यहां एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है जिसमें ये सारी समस्याएं लोगों के प्रतिनिधियों के समक्ष लाई जा सकती हैं और उन पर निष्पक्षता से विचार किया जा सकता है। तर्कसंगत और समझा-बुझाकर विवाद तय करना ही लोक-तंत्रीय ढंग है। गली-मोहल्लों में हिंसात्मक उपद्रव लोकतंत्रात्मक पद्धति की नींव को कमजोर बनाती हैं।

सरकार के लिए यह बड़े ही खेद का विषय है कि देश के कुछ भागों में भाषा के प्रश्न को लेकर प्रदर्शन हों और कानून भंग किये जाएं। सरकार की भाषागत नीति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश में एकता सुदृढ़ हो और लोगों में एकता बड़े और इसके साथ ही समुदाय के तमाम वर्गों को आत्माभिश्चित और सांस्कृतिक विकास के पूरे अवसर दिए जाएं। सरकार को पूरी आशा है कि भाषा के बारे में तमाम विवाद अब समाप्त कर दिए जाएं। हमारी भाषा नीति और कार्यक्रमों पर अमल करने से जो व्यावहारिक समस्याएं उठ खड़ी हों, उन पर समझ-बूझ और आपसी समझौते की भावना से विचार किये जाएं।

सरकार इस बात से आश्वस्त है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समझ-बूझ से राष्ट्रीय हित का साधन निरंतर होता रहेगा। वह अपनी ओर से इसकी पुनः पुष्टि करती है कि वह दलगत संबंधों की परवाह किए बगैर राज्य

सरकारों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहती है। और इसके बदले में वह राज्य सरकारों से सनान सहयोग की अपेक्षा करती है।

संसद् में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ और असम के विभिन्न मतवर्गों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह-मशविरा करके असम के पुनर्गठन के प्रश्न पर आम राय स्थिर करने के लिए सरकार ने बराबर कोशिश की है। उम्मीद की जाती है कि उनके सहयोग से निकट भविष्य में कोई संतोषजनक समाधान निकल आएगा।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, स्वर्गीय मेहर चन्द महाजन ने मैसूर और महाराष्ट्र तथा मैसूर और केरल के बीच सीमा के समझन संबंधी मसले पर अपनी रिपोर्ट पिछले अगस्त में पेश कर दी थी। सरकार का विश्वास है कि ये सीमा समस्याएं संतोषजनक ढंग से सुलझ जाएंगी।

हमारी सीमाओं पर बराबर जो खतरा बना हुआ है उसका मुकाबला करने के लिए हम अपनी रक्षा सेनाओं को लगातार अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं; उन्हें साज-सामान से फिर से लैस करने और उनका आधुनिकीकरण करने का काम बराबर चल रहा है। सुलभ साधनों के अनुसार, समग्र रक्षा योजना के ही अंग के रूप में अपने वायु रक्षा के प्रबंध भी बेहतर किए गए हैं। नौसेना के आधुनिकीकरण करने और जहाजों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी हमने संतोषजनक प्रगति की है। रक्षा उत्पादन की दिशा में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सरकार विशेष प्रयत्न करती रहेगी।

सीमाओं पर दो पड़सियों से खतरा अब भी बना हुआ है। हमउनके साथ मित्रता-पूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध कायम करना चाहते हैं लेकिन अपने देश की प्रादेशिक एकता की

रक्षा के लिए हम जरूरी त्याग करने के लिए तैयार हैं।

शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ और सहयोग के लिए निरंतर प्रयत्न करती रहना अब भी हमारी विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य हैं। हमारे ये उद्देश्य राष्ट्रीय हित से मेल खाते हैं। सरकार का यह विश्वास है कि आज की दुनिया में सिर्फ सह-अस्तित्व का सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है जिसके ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय शांति संभव हो सकती है।

आज दुनिया में संघर्ष और तनाव के अनेक स्रोत हैं। इनमें सबसे खतरनाक वियतनाम और पश्चिम एशिया के संघर्ष हैं। सरकार का विश्वास है कि वियतनाम का दुखद संघर्ष सिर्फ राजनीतिक तरीकों से ही हल किया जा सकता है, संगीन की नोक पर नहीं। इसलिए, सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सबसे पहिले उत्तर वियतनाम पर बमबारी बिना शर्त बंद की जानी चाहिए। संसार के अधिकाधिक देशों की अब यही धारणा बनती जा रही है।

पश्चिम एशिया का संकट अभी तक टला नहीं है। समुचित समाधान में जितनी देर लगेगी उतनी ही यह समस्या ज्यादा पेचीदा बनती जाएगी। सुरक्षा परिषद् के एक सदस्य के रूप में हमने उन सभी प्रयत्नों का निरंतर समर्थन किया है जो इस समस्या का शीघ्र और न्यायोचित समाधान ढूँढने के लिए किए गए हैं ताकि किसी राज्य को आक्रमण से हुए लाभों को अपने पास रखने की इजाजत न दी जा सके और इस क्षेत्र का हर एक राज्य अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक सुरक्षित रह सके।

हमें इस बात की खुशी है कि बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध सीहार्दपूर्ण हैं और उनके साथ आपसी सद्भावना और सहयोग के संबंध

धीरे-धीरे बराबर बढ़ रहे हैं। इन देशों के विशिष्ट नेताओं की भारत यात्रा में श्री प्रधान मंत्री की तथा उनके कुछ दूसरे साथियों की इन देशों की यात्राओं में यह बढ़ता हुआ सीहार्दभाव प्रतिबिम्बित हुआ है।

यह बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संबंध अब भी असंतोषजनक बने हुए हैं। हमने सोचा था कि सत्यनिष्ठ ताश्कंद घोषणा से पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और सहयोग के संबंध विकसित करने का आधार मिल जायेगा। सरकार ने अनेक प्रकार से एक-दूसरे से जुड़े दो पड़ोसी देशों के अनुरूप संबंधों को सामान्य करने की सच्चे हृदय से कोशिश की है। आपसी संपर्कों को फिर से जोड़ने, टूटे हुए संचार सूत्रों को पूरी तरह फिर से स्थापित करने और व्यापार तथा वाणिज्य को फिर से चालू करने से दूसरे मसलों पर विचार करने में सहूलियत होगी। हम आशा करते हैं और हमारा विश्वास है कि बुद्धिमानी और राजनीतिज्ञता से काम लिया जाएगा जिससे कि दोनों देशों के करोड़ों नागरिकों के फायदे के लिये और इस क्षेत्र की शांति और समरसता के हित में मित्रता और समझ-बूझ का ताना-बाना धीरे-धीरे तैयार हो जाए।

जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है हमेशा हमने उतना भला चाहा है, हमारे लिए चीन से इतनी उम्मीद रखना बड़ा स्वाभाविक है कि अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों पर अपनी मर्जी के अनुसार चलने के हमारे अधिकार का वह सम्मान करेगा। परस्पर सम्मान, अनाक्रमण और हस्तक्षेप के सिद्धांतों के अन्तर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का स्थायी आधार मिल सकता है। हम इन सिद्धान्तों पर चीन के साथ अपने संबंध स्थापित करने को हमेशा तैयार हैं।

हमारे देश के लोगों को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाने के आन्दोलन में सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त है। हमने जातीय भेदभाव और दमन की छिनीनी प्रथा समाप्त करने का भी समर्थन किया है। हम दक्षिण रोडेजिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पुर्तगाली उपनिवेशों के दमित लोगों को स्वतंत्रता और मुक्ति दिलाने के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। जो लोग रंगभेद की बर्बर नीति के विकट संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हमारा समर्थन बराबर मिलता रहेगा।

अफ्रीका के स्वतंत्र और प्रभुसत्ता प्राप्त राज्यों के साथ हमारे सम्बंध बहुपक्षीय हो गए हैं। इनमें से कई देशों के साथ हम आर्थिक, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।

यह बड़े संतोष की बात है कि यूरोप में तनाव कम करने की प्रक्रिया बराबर चल रही है। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ खुद हमारे संबंध संतोषजनक रूप से बढ़ रहे हैं चाहे इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था और सिद्धांत कैसे भी क्यों न हों। वे आर्थिक प्रगति के हमारे प्रयत्नों में तरह-तरह से हाथ बटा रहे हैं और इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम उनके साथ व्यापार और आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए बराबर काम करते रहेंगे। सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ और यूगोस्लाविया के साथ हमारे सौहार्द और मित्रता-पूर्ण संबंध हैं। राष्ट्रपति टीटो और अध्यक्ष कोमिगिन की यात्राओं में प्रतिबिम्बित हुए हैं जिनके स्वागत करने की खुशी हाल ही में हमें मिली है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से हमें बहुमूल्य सहायता मिली है जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं और हमें पक्का विश्वास है कि चूंकि हम दोनों शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के हिमायती हैं इसलिए हमारे संबंध निरन्तर बढ़ते ही जाएंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका हमें काफी मात्रा में बहुमूल्य आर्थिक और अनाज की सहायता बराबर दे रहा है जिससे कि विगत में हमें अपनी मुश्किलें आमान करने में सहायता मिली है और जिससे भविष्य में हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने जो सद्भावना दिखाई है और जो सहायता दी है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। यह खुशी की बात है कि अमरीकी महाद्वीप के देशों के साथ हमारी कोई विशेष समस्या नहीं है और उनके साथ हमारे दुतरफा संबंध मित्रता के हैं।

आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे मित्र देशों ने हमें जो आर्थिक सहायता दी है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध संतोषजनक रीति से विकसित हो रहे हैं और हम उनके साथ अपने संबंधों को विशेषकर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सुदृढ़ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बहुत से देश भारत की मित्रता का सम्मान करते हैं, यह उन यात्राओं से प्रकट है कि बहुत से राज्यों के अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा विदेशों के अन्य नेतागण भारत-यात्रा पर आए।

हमें इस बात की खुशी है कि हम दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के मेजबान हैं। आशा की जाती है कि यह सम्मेलन इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक खाई को पाटने के लिए कोई ठोस प्रोग्राम देने में सफल होगा। सरकार को इस बात का पक्का विश्वास है कि आज दुनिया के देशों में अमीरी और गरीबी का जो अन्तर है वही अस्थिरता और तनाव का प्रमुख कारण बना हुआ है और यह शांति और सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है।

घरेलू और विदेशी मामलों का यह विहंगावलोकन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि विधान संघर्षी एवं उन अन्य कार्यों का उल्लेख न किया जाए जो कि आमने-सामने आएंगे।

आगामी 1968-69 के वर्ष के लिए भारत सरकार की आय-व्यय के अनुमान शीघ्र ही आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

सरकार चालू अधिवेशन में निम्नलिखित वैधानिक कार्य संसद् के सामने लाना चाहती है :—

- (1) कम्पनी (संशोधन) बिल, 1968 ।
- (2) सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) अवस्थिति बिल, 1968 ।
- (3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) बिल, 1968 ।
- (4) वायदा संविदा (नियमन) (संशोधन) बिल, 1968 ।
- (5) भारतीय सीमा शुल्क दर की नाम-पद्धति को व्यक्तियुक्त बनाने से संबद्ध बिल ।
- (6) सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों की घेदखली) संशोधन बिल, 1968 ।
- (7) स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) बिल, 1968 ।
- (8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क बिल, 1968 ।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का पहला) को बदलने के लिए एक बिल रखा जाएगा।

संसद् सदस्यगण, मैंने कुछ उत महत्वपूर्ण मसलों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है जो हमारे सामने हैं। सदियों बाद भारत के लोग तेजी से बदलते हुए दौर से गुजर रहे हैं। अपने देश-वासियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का जवाब देने की आज हम सबको चुनौती

मिली है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। सरकार राष्ट्रीय हित और महत्व के प्रमुख मसलों पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर विचार करने और उनकी सलाह लेने के लिए तैयार रहेगी।

संसद् सदस्यगण, आगामी वर्ष में आपको रचनात्मक परिश्रम करना होगा और इन प्रयासों में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ।

(Text : > } the President's Address in English)

Members of Parliament,

I am happy to welcome you to this first session of the New Year.

The past year has been challenging and difficult. The country passed through the second successive year of unprecedented drought and scarcity. Considering the disasters that accompanied famines in the past, we can take justifiable pride in the manner in which the entire nation rose to meet the grave threat posed to the very lives of millions of our countrymen. This was possible because of timely and sustained action by the Central and State Governments; the dedicated services rendered by voluntary organisations; the generous and timely support of friendly nations; the hard work and efficiency of our workers in every concerned field; and above all, the unbending spirit and fortitude of the people of the affected areas themselves.

While a year ago the prospects looked bleak and there were dark forebodings about the future, the clouds are now beginning to lift. The production of foodgrains is expected to be better this year than at any time in the past. Preliminary estimates place production at around 95 million tonnes which would be about 20 million tonnes more than in 1966-67 and 6 million tonnes more than the previous record production of 1964-65. With this

increase in production, the food situation is expected to be easier. However, a significant portion of this crop will naturally go towards filling empty larders or building up depleted inventories. To bring stability to the food situation, it is essential to build up a sufficiently large buffer stock. It is also necessary to maintain a requisite level of public distribution of foodgrains at controlled rates. Towards these ends, Government are maximising efforts at internal procurement and endeavouring to build buffer stocks of the order of 3 million tonnes. All this requires mobilisation of domestic production. In addition, some imports from abroad will still be necessary.

While favourable weather conditions have contributed to the increase in production, there is no doubt that a substantial break-through has been achieved in the field of agricultural production by the use of improved techniques. While in 1966-67 five million acres were sown with high-yielding varieties of seeds, 6 million acres were covered in the last Kharif season alone and a further 9 million acres are expected to be covered in the current Rabi season. Production of commercial crops like cotton, jute, sugarcane, tobacco, groundnuts is also expected to increase. The minor irrigation programme will cover an additional area of over 3 million acres. There has been an impressive increase in the use of fertilisers; thus the consumption of nitrogenous fertilisers in the current year will be about twice that in 1965-66. The area covered by plant protection measures this year is expected to be about three-quarters more than last year. There have been striking increases in the supplies of tractors, power tillers, pumps, diesel engines and improved implements to farmers. The arrangements for supply of agricultural credit have been strengthened. Progress continues to be made in the implementation of programmes of agricultural education, training, research and extension. The development programme

for agriculture aims at securing national self-sufficiency in foodgrains within the shortest possible time.

The increased agricultural production has resulted in a substantial increase in national income, which is expected to be about 10-8 per cent, higher in the current year than in 1966-67. Improved agricultural performance has also reduced the upward pressure on prices. Over the year as a whole, the increase in wholesale prices was 5-7 per cent, as against 16 per cent, during 1966. While the prospects of achieving a reasonable measure of price stability are good, it will be necessary as I have already said, to continue with the system of public distribution of foodgrains and to exercise discipline in respect of fiscal, monetary and income policies.

The severe drought of the last two years adversely affected industrial output because industries based on agriculture could not secure adequate supplies of raw material and there was also a fall in demand due to reduction in incomes. Some capital and producers goods industries faced slackened demand because of restricted investment outlays. The slowing down of industrial expansion has affected employment opportunities particularly for skilled manpower. Selective measures were adopted by Government to stimulate the output of goods both for export and for the domestic market; these included the selective liberalisation of credit, placing of advance orders by public sector undertakings, and avoidance of import of items which could be manufactured indigenously. Improved agricultural production and the consequent rise in national income are expected to stimulate demand for a variety of industrial products during the coming year.

The persistent upward movement of cost and prices, together with the sharp decline in agricultural production during the last two years, adversely affected the competitiveness of our exports. However

with increased production of foodgrains and of agricultural raw materials for industry, the outlook for exports in the coming year is encouraging. In the first seven months of the current financial year, exports were 577 per cent, higher than in the corresponding period of 1966-67. The engineering industries have secured substantial export orders. As industrial production picks up, it is to be hoped that we shall be able to produce more for overseas markets.

Government continue to help producers and manufacturers to increase and diversify production and develop marketing skills and competence. The endeavour to improve export opportunities for our products and induce importing countries to provide favourable conditions for them has been pressed through multilateral negotiations, bilateral agreements and the day-to-day contacts of our missions abroad. The Agreements reached with the Socialist countries will help to sustain the expansion which has been achieved in our trade with them. The successful completion of the Kennedy round of negotiations will bring to our exporters new opportunities for the export of some of our goods to Market economies. The Tripartite Economic Co-operation Agreement concluded with the U.A.R. and Yugoslavia will help to increase our mutual trade and provide a basis for expanding the area of commercial co-operation with other developing countries. The expansion of exports remains a national objective of the highest priority and will be pursued with vigour.

The adverse balance of trade and the substantial burden of debt servicing combined with unavoidable imports of foodgrains and raw materials for exports production, have continued to make our foreign exchange position difficult over the year. Government have sought the co-operation of friendly countries and international institutions in finding a solution to the debt service problem. A measure of assistance to relieve the burden of debt was obtained during the year and further dis-

cussions continue. Nevertheless, there was a decline in the foreign exchange reserves and it became necessary to obtain further short-term assistance from the International Monetary Fund.

In any scheme for promoting a more efficient handling of our international trade, the development of our merchant shipping and port facilities occupies a place of crucial importance. In this respect Government have taken a number of important steps, including development of Tuticorin and Mangalore ports, construction of Haldia docks, expansion of the facilities at the existing major ports, reorganisation and modernisation of Hindustan Shipyard and the setting up of a second Shipyard in the public sector at Cochin for the construction of bulk carriers of 66,000 dead weight tons with facilities for repairs to ships up to 85,000 dead weight tons. As for our merchant shipping, the tonnage has now reached a total of approximately two million gross registered tons. Government has set up a Commission to examine comprehensively the problems relating to the finances and economics of major ports, including their modernisation.

No annual survey will be complete without reference to the vitally important programme of Family Planning. This programme made rapid strides during the year. Its acceptability spread to many new sections of rural as well as urban population. Over 2.85 million men and women are estimated to be covered under the various family planning programmes. This represents the highest figure reached in any single year so far. However, in order to reach the objective of reducing the annual birth rate from approximately 40 per thousand to 25, an even greater and sustained effort will be required. With this end in view, it is proposed to bring over 6 million additional couples within the ambit of family planning methods and services during the next year. Government have also under consideration certain other measures vitally related to population control.

As one looks to the future, the foremost task which the Government have set themselves lies in imparting a new dynamism to the economy which is recovering from the severe set-backs suffered during the last two years. Government believe that it is only through the process of planning that the difficulties can be overcome and the country can go forward in its social and economic development.

The Planning Commission is engaged in the formulation of the Fourth Five-Year Plan which will now commence from April 1969. Meanwhile, planning for development has been on the basis of Annual Plans. The Annual Plan for 1968-69 will be shortly laid before you. Both the Government and the Planning Commission were naturally anxious that the Plan should be ready in time to be incorporated in the Budget for 1968-69.

The formulation of our Plans calls for an examination of a number of questions. Among these the most important relate to mobilisation of resources, increasing the efficiency and productivity of public sector enterprises and the proper utilization of science and technology. There cannot be adequate mobilization of internal resources without a much higher rate of domestic savings, both public as well as private. This, in turn, presupposes a regime of self-denial and self-restraint without which we cannot move forward. In order to stimulate effective mobilisation of resources, Government are considering various measures to simplify tax laws, rationalise taxation procedures and streamline the collection machinery.

Government are conscious of the need for urgently raising the efficiency of the public sector. They are reviewing the organisation and working of this sector in the context of the advice tendered by several expert bodies. Among the aspects under special examination are better management, a more rational and a carefully thought out personnel policy, improved labour relations and effective economies

through a more rigorous enforcement priorities and evaluation.

Members will recall that during the last session of Parliament, the Deputy Prime Minister made a statement on Government's decision to bring general insurance under social control. In the current session, Government propose to introduce a bill to give effect to the decisions contained in that statement.

I referred to the importance which Government attach to the application of Science and Technology to our economic development. With this end in view, Government's policy is to bring together, in productive and creative partnership, our scientific research establishments, governmental machinery and industry.

During the year under review, the Thumba Equatorial Rocket Launching Station was formally dedicated. The first Rohini rocket developed at the centre was successfully launched from Thumba. The experimental Satellite Communication earth Station at Ahmedabad has been completed and a *new* station will be set up at Arvi. In the field of nuclear power, the Tarapore Atomic Power Project is expected to be commissioned this year. Two more nuclear power stations are under construction.

Government are conscious of the fact that our administrative structure must not only respond to changing needs but also command the confidence of the people. In order to achieve these purposes, the Administrative Reforms Commission was set up. It has produced a series of reports which have evoked wide interest. It is for the first time that a comprehensive enquiry of this kind has been undertaken in our country. The Commission had addressed itself to the problem of redressing grievances of citizens and had made certain recommendations. Government have now decided to set up a statutory machinery to enquire into complaints alleging corruption or injustice arising out of maladministration

The machinery will be headed by a Lokpal who will have authority to enquire into the allegations arising out of administrative acts of Central Ministers and Secretaries. The Lokpal will also co-ordinate the working of two other functionaries of the status of Lokayuktas. The first will primarily go into allegations of corruption and the second into other allegations made against Central Government servants lower in rank than Secretaries. A Bill on the subject will be introduced in Parliament during the present session.

There are certain aspects of our national life which are a source of constant concern to Government. Unemployment, specially amongst educated and technically qualified youth, is naturally a matter of disquiet. However, there are no easy, short-term solutions. These problems can only be solved in the measure that our economic growth provides increase in employment opportunities which will absorb the output of our educational and technical institutions as well as take care of population increases. The Planning Commission is critically re-examining the earlier forecast of our manpower requirements. In the meantime, Government earnestly hope that our young men and women, conscious of the dignity of labour, will not hesitate such employment opportunities as might be available at present even if the work involved does not measure up to their technical qualifications.

The socio-economic advancement of the hitherto under-privileged sections of our society—the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward Classes, remains a matter of the utmost interest and concern to Government. While a great deal has been done to ameliorate their position, Government are conscious that more remains to be done. In this respect, the final answer to our problem lies in the speedy growth of our economy.

Both in the short-term and in the longer perspective, all our hopes for economic

recovery and further growth depend on orderly functioning of our democratic institutions, the hard work of our people, their sense of self-discipline, the productivity of their labour and the maintenance of industrial peace.

It is a matter of concern that there has been a recrudescence of divisive forces causing conflicts and violence either in the name of region, or language or community. This is a matter for deep national concern transcending party affiliations. It was in recognition of this that both Houses of Parliament had given their unqualified support to efforts being made to curb communalism. The appointment of a Commission of Inquiry headed by a former Judge of the Supreme Court to enquire into the major incidents that took place in different parts of the country in recent time, reflects Government's determinations to do everything that lies within its power to curb the forces of disruption.

In a country as large as ours, there will always be problems which agitate people in one part or the other. However, we have a political system in which all these problems can be brought up for dispassionate consideration by the representatives of the people. Reasoned debate and persuasion are the only ways of democratic functioning. Violent agitation in the streets weakens the democratic system and undermines the foundations of national unity.

It is a matter of deep regret to Government that there should be demonstrations and acts of lawlessness over the language issue in certain parts of the country. The overriding objective of Government's language policy is to strengthen the unity of the country and to promote the integration of our people, while providing full opportunity to all sections of the community for self-expression and cultural development. It is Government's earnest hope that all controversies about language will now be ended. Whatever practical problems arise in the implementation of our language

policy and programmes should be approached in a spirit of understanding and mutual accommodation.

Government are convinced that co-operation and understanding between the Central and State Government's will continue to serve and advance the larger national interest. On their part, they reaffirm their desire to work in harmony with State Governments irrespective of party affiliations. And, in turn, they expect similar co-operation from State Governments.

Government have made earnest effort to evolve a national consensus on the question of reorganisation of Assam in consultation with leaders of various political parties in Parliament, and the representatives of different sections of opinion in Assam. It is hoped that with their co-operation a satisfactory solution will be found in the near future.

The late Shri Miliar Chand Mahajan, former Chief Justice of India, submitted his report in August last on the question of boundary adjustment between Mysore and Maharashtra and Mysore and Kerala Government trust that these boundary problems will be satisfactorily resolved.

To meet the persistent threats on our borders, we are continuing to improve the state of preparedness of our Defence Forces, their re-equipment and modernisation are proceeding steadily. Within the resources available, our air defence arrangements have also been improved as part of the overall Defence Plan. Modernisation of the Navy and expansions of our ship holdings have made good progress. Government will continue the special efforts to promote self-reliance in the field of Defence Production.

The threats across our borders from two of our neighbours continue. While we seek friendly and peaceful relations with them, we are determined to make the necessary sacrifices, in defence of the territorial integrity of the country.

The steadfast pursuit of peace, international understanding and cooperation continue to be the basic objectives of our foreign policy. These objectives coincide with our enlightened national interest. Government are convinced that in the present-day world, the principles of coexistence alone provide the frame work for international peace.

In the world today, there are many sources of conflict and tension. The most dangerous of these lie in Vietnam and West Asia. Government are convinced that the tragic conflict in Vietnam can only be resolved by political and not by military means. Government have, therefore, consistently appealed for an unconditional stoppage of the bombing of North Vietnam as the first step towards a peaceful settlement. An increasing number of countries in the world subscribe to this view.

The crisis in West Asia remains unresolved. The longer a just solution is delayed, the more difficult would be the problem. As a member of the Security Council we have consistently supported all the efforts made to find an early and equitable settlement so that no State is allowed to retain the fruits of aggression and that every State in the area is able to live in peace and security with its neighbours.

Nearer home, we are glad that our relations with Burma, Ceylon, Nepal and Afghanistan are cordial and the areas of mutual understanding and co-operation with them are being steadily enlarged. This growing cordiality has been reflected by the visits of the distinguished leaders of these countries to India, and the visits of the Prime Minister and some of her colleagues to these countries.

It is a matter of regret that our relations with Pakistan and China remain unsatisfactory. We had hoped that the solemn Declaration of Tashkent would provide a basis for the development of peaceful and co-operative relations with Pakistan. Go

vernment have earnestly tried to bring about a normalisation of these relations as befits two neighbouring countries with so many ties in common. The restoration of mutual contacts, the full re-establishment of the severed communications and the reactivation of trade and commerce will facilitate the consideration of other questions. We hope and trust that wisdom and statesmanship will prevail, so that the fabric of friendship and understanding is gradually built up for the benefit of the hundreds of millions of citizens of both countries and in the interest of peace and harmony in the area.

As for our relations with China, we have always wished the Chinese people well. We naturally expect China to respect our right to pursue our own domestic and foreign policies. The principles of mutual respect, non-aggression and noninterference alone provide a durable basis for international relations. On our part, we seek restoration of our relations with China on these principles.

Our country had the honour of being in the vanguard of the movement for the liberation of people from colonial rule. We have also stood for the ending of the odious practice of racial discrimination and oppression. We shall continue to espouse the cause of the suppressed peoples of Southern Rhodesia, South West Africa and of the Portuguese colonies for their independence and liberation. To those struggling against the barbarous policy apartheid, our unrelenting support shall continue.

Our relations with the sovereign and independent States in Africa have become many-sided. We are actively collaborating with a number of these States in economic, technical and educational fields.

It is gratifying to note that the process of detente in Europe continues. Our own relations with the European nations, regardless of their political systems and ideologies, are growing satisfactorily. In

different ways, they are partners in our efforts at economic progress for which we thank them. We shall continue to work for the strengthening of our trade and economic relations with them. The continuing cordiality and friendliness of our relations with the U. S. S. R. and Yugoslavia have been reflected in the visits of President Tito and Chairman Kosygin, whom we had the pleasure to receive in our midst recently. We have received valuable assistance from the U. S. S. R. for which we are grateful, and are confident that with our common dedication to the principles of peaceful co-existence our relations will continue to flourish.

The U. S. A. continues to extend to us valuable and substantial economic and food aid which has helped us to tide over difficulties in the past and should assist us in the growth of our economy in the future. We are grateful for their understanding and help. With the countries in the American Continents, we have happily no special problems and our bilateral relations with them are friendly.

We are thankful to Australia, Britain, Canada, France, Japan, the Federal Republic of Germany and other friendly countries for their economic help.

Our relations with the countries of South and South East Asia are developing satisfactorily and we look forward to further strengthening of our ties with them, more specially in the sphere of economic co-operation.

That the friendship of India is valued by many countries is evident from visits paid to us by distinguished Heads of State and Government and other leaders from various countries.

We are glad to be hosts to the second United Nations Conference on Trade and Development. It is to be hoped that this Conference will succeed in giving to the international community a concrete programme of action designed to bridge the

increasing economic gap between developed and developing nations. Government are deeply convinced that the present wide disparities between the rich and poor nations constitute the foremost cause of instability and tension in the world today and pose a threat to peace and security.

This broad survey of our internal and external affairs will not be complete without a reference to the legislative and other business which will come up before you.

The estimates of receipt and expenditure of the Government of India for the next financial year 1968-69 will be presented to you for consideration shortly.

It is the intension of Government to bring before Parliament the following legislative measures during the current session:—

(1) The Companies (Amendment) Bill, 1968.

(2) The Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill, 1968.

(3) The Central Silk Board (Amendment) Bill, 1968.

(4) The Forward Contracts Regulation (Amendment) Bill, 1968.

(5) Bill to rationalise the nomenclature of the Indian Customs Tariff.

(6) The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 1968.

(7) The Gold Control (Amendment) Bill, 1968.

(8) The Central Excises Bill, 1968.

A Bill will be introduced to replace the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1968 (No. 1 of 1968).

Members of Parliament, I have briefly touched upon some of the more important issues before us. After many centuries, the

people of India are going through a process of dynamic change. It is a challenge to us all to answer the urges and needs of our people. Important national problems must be placed above party politics. Government will be ready to sit with Leaders of all Parties and take counsel with them on major issues of interest and importance to the nation.

May I now commend you to another year of constructive labour and wish you success in your endeavours?

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: Before we take up the business on the Order Paper, I wish to draw the attention of Members to the passing away of one of our ex-Members, Hafiz Mohammed Ibrahim, Shri Deen Dayal Upadhyaya and Shri M. S. Aney.

Hafiz Saheb, as he was affectionately called, was born at Nagina in U. P. in 1889. After education at Rampur and Aligarh he practised as a lawyer at Nagina, Bijnor and Moradabad for over 20 years. He took an active part in our freedom struggle, in the Khilafat movement and suffered imprisonment several times. He served in the U. P. Cabinet from 1937 to 1939 and again from 1946 to 1958 and held charge of several Departments. He became a Member of the Central Cabinet in 1958 and functioned in that capacity till 1964. During this period he was a Member of our House and was also its Leader for some time. He was later appointed Governor of Punjab. A staunch nationalist, a good Parliamentarian and a sincere worker in the cause of Hindu-Muslim unity, he earned the respect and affection of one and all. In his passing away we have lost an eminent leader.

It is with profound sorrow and a sense of shock that I refer to Shri Deen Dayal Upadhyaya, who died in most tragic circumstances in the early hours of yesterday.